

[This question paper contains 10 printed pages.]

1242

Your Roll No.

आपका अनुक्रमांक _____

LL.B

JS

III Term

Paper LB-301 – CONSTITUTIONAL LAW-I

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 100

समय : 3 घण्टे

पूर्णांक : 100

(Write your Roll No. on the top immediately
on receipt of this question paper.)

(इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही उपर दिए गए निर्धारित
स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।)

Note :- Answers may be written either in English or in Hindi; but
the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी :- इस प्रश्नपत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी किसी एक भाषा में
दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

Attempt any Five questions Including
Question No.1 which is compulsory
All questions carry equal marks.

अनिवार्य प्रश्न क्रमांक 1 सहित
कुल पाँच प्रश्न कीजिये।
सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

P.T.O.

1. Answer briefly any four of the following :

निम्नलिखित में से किन्ही चार के उत्तर संक्षेप में लिखिए :

- (a) Can parliament impose a tax which is not specifically enumerated in the seventh schedule ?

क्या संसद ऐसा कर भी अधिरोपित करती है जिसको सातवीं अनुसूची में विशेष रूप में उल्लिखित नहीं किया गया है ?

- (b) Explain the doctrine of territorial nexus.

राज्य क्षेत्रीय अभिवन्ध के सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिए ।

- (c) Curative petition.

शोधक याचिका

- (d) Can a person disqualified from being a member of a legislature assembly be appointed as a chief Minister ?

क्या उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए निरहित हो ?

- (e) Can the president promulgate an Ordinance on a matter not enumerated in the union or concurrent list ? What are the constitutional limitations on the ordinance making power ?

क्या राष्ट्रपति उस मामले पर अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जो संघ या समवर्ती सूची में उल्लिखित नहीं है । अध्यादेश निर्माण शक्ति की क्या-क्या संविधानिक परिसीमाएं होती हैं ?

- 2 (a) Is the power to code territory within the competence of the executive and/or the Parliament? Explain with reference to relevant constitutional provisions and case law.

क्या राज्यक्षेत्र को अर्पित करने के अधिकार के प्रयोग के लिए कार्यपालक सक्षम है और/या संसद सक्षम है। सुसंगत साविधानिक उपबन्धों और निर्णय विधि के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए।

- (b) (i) The second schedule of the constitution describes the extent of the union Territory of Andaman & Nicobar Islands as the territory which immediately before the commencement of the constitution comprised the chief commissioner's Province of the Islands. In 2005, the tsunami that hit India submerged Indira Point, the southernmost tip of the Islands. Does this constitute "cession" of Indian territory and require any amendment of the second schedule?

संविधान की दूसरी अनुसूची में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्यक्षेत्र का विस्तार इस रूप में वर्णित है - वह राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले अंडमान और निकोबार द्वीप के मुख्य आयुक्त वाले प्रान्त में समाविष्ट था। 2005 में जो सुनामी भारत से टकराई थी उसने द्वीपसमूह के दक्षिणतम सिरे - "इन्दिरा प्वाइन्ट" को जलमग्न कर दिया था। क्या यह भारतीय राज्यक्षेत्र का "अर्पण" है तथा क्या इसके कारण द्वितीय अनुसूची का संशोधन अपेक्षित है ?

- (b) (ii) Elucidate the constitutional procedure that must be followed if a certain area falling within the territory of Nepal is acquired by the central government and this area is to be merged with the territory of Uttar Pradesh.

उस संविधानिक प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसको तब अपनाया होगा यदि नेपाल के राज्यक्षेत्र में पड़ने वाले कतिपय क्षेत्र का केन्द्र सरकार द्वारा अर्जन किया जाता है तथा इस क्षेत्र को उत्तर प्रदेश के राज्यक्षेत्र के साथ मिला दिया जाता है।

3. The Chief Minister of state X, upon the completion of 3 years of 5 years tenure of his government recommends to the Governor of the state the dissolution of the legislature assembly and holding of elections on the ground of seeking a fresh mandate from the people. The Governor refers to dissolve the legislative assembly on the ground that the entire period of 5 years of the state government has not elapsed and instead recommends imposition of President's rule under Article 356 of the constitution.

Discuss the validity of the governor's actions in the light of constitutional principles and case law. What is the extent of judicial review exercisable by the courts in such cases ?

राज्य X का मुख्यमंत्री अपनी सरकार के पाँच वर्ष के शासन काल में से 3 वर्ष के पूरा होने पर राज्य के राज्यपाल से विधान सभा भंग किए जाने और चुनाव आयोजित किए जाने की इस आधार

पर सिफारिश करता है कि लोगों से नया जनादेश प्राप्त किया जाए। राज्यपाल इस आधार पर विधान सभा को भंग करने से इनकार कर देता है कि राज्य सरकार के कार्यकाल की पाँच वर्ष की पूरी अवधि व्यतीत नहीं हुई है तथा वह इसके बजाय संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने की सिफारिश कर देता है।

संविधानिक सिद्धान्तों तथा निर्णय विधि के प्रकाश में राज्यपाल की कार्रवाई की विधि मान्यता का विवेचन कीजिए। ऐसे मामलों में न्यायालयों द्वारा प्रयोज्य न्यायिक पुनर्विलोकन की क्या सीमा होती है ?

4. (a) Distinguish the procedure followed by courts in public interest litigation in contrast to the procedure followed in adversarial proceedings.

न्यायालयों द्वारा प्रतिकूल कार्यवाहियों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा उसके विपरित लोकहित के मुकदमों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में जो भेद किया जाता है उसको स्पष्ट कीजिए।

- b. Can a petitioner who has unsuccessfully approached a high court under Article 226 be permitted to move the supreme court under Article 32 of the constitution through a petition on the same facts and for obtaining the same or similar remedy ? Discuss.

क्या किसी ऐसे याचिकाकर्ता, को जिसने संविधान अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय के पास असफल पहुँच की थी, उसी या उसी के अनुरूप उपचार प्राप्त करने हेतु उन्हीं तथ्यों के आधार पर याचिका

के जरिये संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने की अनुमति दी जा सकती है ? विवेचन कीजिए ।

5. Discuss the constitutional validity of the following applying the relevant rules of constitutional interpretation.

संविधानिक निर्वचन के सुसंगत नियमों को लागू करते हुए निम्नलिखित की संविधानिक विधिमान्यता का विवेचन कीजिए :

- a. State Y enacts a law under entry 6, List II "Public health and sanitation, hospitals and dispensaries", restricting the use of loudspeakers near hospitals. Mr. A upon being prosecuted for violating the law challenges the competence of the state legislature to enact such a law on the ground that it encroaches on entry 31, List I "Broadcasting and other forms of communication" which is within the exclusive domain of parliament.

Y राज्य सूची II की प्रविष्टि 6 - "लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय के अधीन एक विधि अधिनियमित करता है जिसके द्वारा अस्पतालों के निकट लाउडस्पीकों के प्रयोग को निर्बन्धित कर दिया गया । उक्त विधि के उल्लंघन हेतु अभियोजित किए जाने पर मिस्टर A ऐसी विधि अधिनियमित करने के लिए राज्य विधानमंडल की सक्षमता को इस आधार पर आक्षेपित करता है कि इससे सूची I की प्रविष्टि 31 - "प्रसारण और अन्य संचार साधन" का अधिक्रमण होता है जो संसद के अनन्य कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत है ।

- b. State Z enacted a law for holding a common entrance test to select candidates for professional course in the state. This law is challenged on the ground that

interferes with the legislative power of union parliament under Entry 66, List I

Entry 66, List I : Coordination and determination of standards in institutions of higher education

Entry 25, List III: Education, including technical, education medical education and universities subject to the provisions of entries 63,64,65 and 66 of List I.

Z राज्य ने अपने यहां व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए साझी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने हेतु एक विधि अधिनियमित की। इस विधि को इस आधार पर आक्षेपित किया गया है कि इससे सूची I की प्रविष्टि 66 के अधीन संघीय संसद की विधायी शक्ति में हस्तक्षेप होता है।

सूची I, प्रविष्टि 66 : उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में मानकों का समन्वय तथा अवधारण।

सूची III, प्रविष्टि 25 : सूची I की प्रविष्टि 63,64,65 और 66 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए शिक्षा जिसके अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा, आयुर्विज्ञान शिक्षा और विश्वविद्यालय है।

6. (a) What is repugnancy? What are the different situations when repugnancy can arise under Article 254 of the constitution?

प्रतिकूलता क्या होती है? वे क्या भिन्न-भिन्न स्थितियां हैं जब संविधान के अनुच्छेद 254 के अधीन प्रतिकूलता सामने आ सकती है।

P.T.O.

- (b) Parliament enacted the Hindu succession Act in 1956 which recognised only limited rights of daughters as compared to sons in joint family property of a deceased male Hindu. The state of Andhra Pradesh amended the said Act in 1985 which treated daughters as coparceners provided that their marriage had not been performed before 5.9.1985. Subsequently Parliament amended the Hindu succession Act in 2005 which provided that irrespective of the date of marriage, all daughters would be deemed to be coparceners. The parliament while amending s.6 of the Hindu succession Act, 1956 did not repeat the Andhra Pradesh Amendment Act.

What is the effect of the 2005 central amendment regarding the rights of married daughter in the state of Andhra Pradesh? Discuss.

संसद ने 1956 में हिन्दू, उत्तराधिकार अधिनियम का अधिनियमन किया था जिसमें मृतक हिन्दू पुरुष की संयुक्त कुटुम्ब सम्पत्ति में पुत्रों की तुलना में पुत्रियों के केवल सीमित अधिकारों को मान्यता दी गई थी, आन्ध्र प्रदेश राज्य ने उच्च अधिनियम को 1985 में संशोधित कर दिया जिसमें पुत्रियों को सहदायिक माना गया बशर्ते कि उनका विवाह 5.9.1985 से पहले नहीं हुआ हो। बाद में संसद ने 2005 में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम को संशोधित कर दिया गया। इसमें उपबन्ध किया गया कि विवाह कि तारीख पर विचार किए बिना सभी पुत्रियों को सहदायिक माना जाएगा। संसद ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 को संशोधित करते हुए आन्ध्र प्रदेश के संशोधन अधिनियम को निरस्त नहीं किया।

आन्ध्र प्रदेश राज्य में नामित पुत्रियों के अधिकारों के सम्बन्ध में 2005 के केन्द्रीय संशोधन का क्या प्रभाव हुआ है ? विवेचन कीजिए ।

7. (a) Regulatory measures and compensatory taxes are outside the scope of Article 301 of the constitution. Discuss this statement with reference to decided cases.

नियामक उपाय और प्रतिकारी कर संविधान के अनुच्छेद 301 की व्याप्ति से बाहर हैं । विनिश्चित कसों के संदर्भ में उक्त कथन का विवेचन कीजिए ।

- b. State B issued a notification under the State Sales Tax Act exempting new units manufacturing television sets within the state from paying sales tax for a period of 3 years from the date of setting up of the manufacturing unit in the state. This notification is challenged as *ultra vires* the constitution. Decide the validity of the said notification in the light of relevant case law.

राज्य B ने राज्य बिक्रीकर अधिनियम के अधीन अधिसूचना जारी की जिसमें राज्य में विनिर्माण इकाई स्थापित करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक राज्य में टेलीविजन सैट विनिर्माण करने वाली नई इकाईयों को बिक्री कर अदा करने से छूट दि गई । इस अधिसूचना को संविधान के *अधिकारातीत* बताते हुए आक्षेपित किया गया है । सुसंगत निर्णय विधि के प्रकाश में उक्त अधिसूचना कि विधि मान्यता का विनिश्चय कीजिए ।

8. Article 1 of the constitution describes India as a union of states, rather than as a federation comment critically on the nature of Indian federalism, in the light of constitutional provisions and divided cases.

संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ लिखा गया है न कि एक परिसंघ। संविधानिक उपबन्धों और विनिश्चित कसों के प्रकाश में भारतीय परिसंघ के स्वरूप पर समीक्षात्मक टिप्पणी लिखिए।